

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 160/2018/225 आरटीए

1. गुरलाल सिंह पुत्र जलौर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. जलौरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्ट

—: बनाम :-

1. इकबाल सिंह पुत्र गुरजन्तसिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. गुरलाल सिंह पुत्र गुरजन्तसिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. हरपाल सिंह पुत्र गुरजन्तसिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोंडेंटस

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 09.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्र0सं0 153/2017 अनवानी इकबालसिंह आदि बनाम गुरलालसिंह आदि

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री वतनदीप सिंह राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 2 व 3

निर्णय

दिनांक -03.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेंटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत करते हुए इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2017 को अन्तरिम आदेश जारी किया जाकर अप्रार्थीगण चक 6 डीएलपी के खाता सं. 19/18 प.न. 143/194 के मु.न. 48 के कि.न. 18 ता 20 में अप्रार्थीगण/अपीलान्टस दखलअंदाजी से निषेध रहने व मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त अन्तरिम आदेश अपीलाधीन आदेश के जरिये ताफैसला दावा कन्फर्म किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार की सूचना दिये दिनांक 09.05.2018 को पत्रावली कैम्प कोर्ट मोरजण्ड सिखान में पेशी में ली जाकर एकपक्षीय अपीलांटस को सुने बिना आदेश पारित किया गया है। पूर्व में चक 6 डीएलपी के प.न. 143/194 मु.न. 48 की 8 बीघा भूमि वर्ष 2001 में खातेदारान हरनेकसिंह, टेकसिंह व करनैलसिंह उर्फ फरनैलसिंह पुत्रगण जोगेन्द्रसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित थी जो उक्त तीनों खातेदारों द्वारा दिनांक 30.04.2001 को गुरतेजसिंह पुत्र खेतासिंह को सप्रतिफल विक्रय कर दी तथा उक्त भूमि की पूर्व दिशा की ओर पत्थरलाईन अर्थात् प.न. 142/194 में अवस्थित मंजूरशुदा रास्ते से आने हेतु उक्त 8 बीघा भूमि को कोई रास्ता नहीं लगता था। उक्त भूमि क्रेता गुरतेजसिंह द्वारा विक्रय अनुबंधित भूमि जो प. न. 143/194 के मु.न. 48 कि.न. 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 में अवस्थित था, तत्पश्चात् दिनांक 15.05.2002 को हरनेकसिंह आदि द्वारा एक विक्रय विलेख गुरतेजसिंह के पक्ष में निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया। उक्त भूमि में आने जाने हेतु एक अन्य खातेदार गुलाम फरीद पुत्र अब्दुल हक जिसकी भूमि भी इसी मुरब्बा नं. 48 के कि.न. 18, 19, 20 में अवस्थित थी, में से उत्तर दिशा की ओर उक्त क्रेता गुरतेजसिंह द्वारा उक्त भूमि में आने जाने हेतु तीनों बीघों में दो दो बिस्वा भूमि यानि कुल 6 बिस्वा गुलाम फरीद से प्रतिफल क्रय कर ली जिसका पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 25.02.2002 को गुलाम फरीद बहक गुरतेजसिंह उपपंजीयक संगरिया कार्यालय से पंजीबद्ध करवा दिया। विक्रय विलेख के रोज से ही उक्त भूमि पर काबिज होकर रास्ता के रूप में अपनी खातेदारी भूमि का व्यक्तिगत रूप से उपयोग व उपभोग करने लगा तथा उक्त दोनों विक्रय विलेखों के आधार पर उक्त 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि का नामान्तरण भी गुरतेजसिंह के नाम से हो चुका है तथा गुलाम फरीद

द्वारा दिनांक 25.02.2002 को एक हलफनामा रोबरू गवाहान लिखवाकर निष्पादित किया कि चक 6 डीएलपी के प.न. 143/194 मु.न. 48 कि.न. 18, 19, 20 में 2-2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा भूमि गुरतेजसिंह पुत्र खेतासिंह को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख विक्रय की है तथा उक्त वर्णित रकबे का कब्जा सौपा है तथा यह रकबा क्रेता द्वारा रास्ते के लिए क्रय किया है, बाबत दिया। तत्पश्चात दिनांक 28.01.2005 को गुरतेजसिंह द्वारा उक्त दोनो बैयनामो में क्रय की आराजी अप्रार्थी सं. 2/अपीलांट सं. 2 को विक्रय अनुबंधित कर कब्जा कुल भूमि का मौके पर उसी दिन अप्रार्थी सं. 2 को सौंप दिया तथा दिनांक 17.03.2007 को विक्रय विलेख अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया। उपरोक्त तथ्यों से साबित होता है कि उक्त कि. न. 18 ता 20 में उतरी छोर पर दिनांक 25.02.2002 से रास्ता चला आ रहा है जो अप्रार्थी सं. 2 को विक्रय अनुबंध व विक्रय विलेख के माध्यम से खातेदारी भूमि के रूप में निहित हुआ है, आदि आदि तथ्यों पर अपीलांटस द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब पेश किया था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों का विश्लेषण अपने आदेश में नहीं किया है।

4. रेस्पोंद द्वारा एक राजस्व वाद अनवानी हरमेलसिंह आदि बनाम बलदेवसिंह आदि, वाद संख्या 18/2013 द्वारा चक 6 डीएलपी के प.न. 143/194 मु.न. 48 के कि.न. 18 ता 20, अप्रार्थी सं. 2 की उतरी दिशा की 6 बिस्वा खातेदारी भूमि को शामिल करते हुए अपनी खातेदारी घोषित करने का अनुतोष चाहते हुए विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा अपीलांट सं. 2 की तामिल बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए दिनांक 10.02.14 को निर्णय करवाकर डिक्री करवा लिया, जिसके विरुद्ध एक अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ में प्रस्तुत की तथा राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 23.09.2016 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण सहायक कलेक्टर महोदय

संगरिया को प्रतिप्रेषित कर दिया, जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जिसका क्रमांक 7161/2016 है0 जो वर्तमान में लम्बित है तथा उक्त प्रकरण के पूर्व में लम्बित होने के कारण प्रार्थीगण वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है तथा रेस्पो0 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र चक 6 डीएलपी के खाता सं. 19/18 के आधार पर प्रस्तुत किया है जबकि उक्त जमाबंदी राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2016 के अनुसार निष्प्रभावी हो चुकी है। उक्त तीनों बीघों की भूमि का सम्पूर्ण भू-भाग रेस्पो0 की खातेदारी का ही है तथा एक खातेदार काश्तकार स्थाई निषेधाज्ञा का वाद कानूनन प्रस्तुत कर सकता है। स्थाई निषेधाज्ञा का वाद एक सहखातेदार, दूसरे सहखातेदार के विरुद्ध कानूनन पेश नहीं कर सकता है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 23.09.2016 के अनुसरण में अपीलांटस व रेस्पो0 सहखातेदार है तथा कानूनन एक सहखातेदार के विरुद्ध विशिष्ट बीघों की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान ना देकर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 की कृषि भूमि चक 6 डीएलपी के खाता सं. 19/18 में प.न. 143/193 मु.न. 30 कि.न. 22 ता 24/0.759 है0, प.न. 143/194 मु.न. 48 कि.न. 9 ता 12/1.012, 18/0.127, 19 ता 22/1.012, प.न. 144/195 मु.न. 50 कि.न. 21 ता 24/1.012, 25/0.228 है0, 143/196 मु.न. 61 कि.न. 4 ता 7/1.012, 14, 15/0.506 है0, 144/196 मु.न. 62 कि.न. 1 ता 4/9/2, 5/0.202, 6/0.228, 7 ता 14/2.024, 15/0.228 कुल 2.262 है0 रास्ता मय गै.मु. 0.102 खाला 0.126 है0

कुल 9.490 है० भूमि है। उक्त भूमि रेस्पो० के पिता गुरजन्तसिंह की खरीदशुदा है। रेस्पो० के पिता गुरजन्तसिंह फौत हो चुका है उनके बाद समस्त भूमि रेस्पो० के कब्जा मे चली आ रही है। उक्त भूमि मे प.न. 143/194 मु.न. 48 कि.न. 18/0.127, 19/0.253, 20/0.253 पूरे है। इनके से कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है लेकिन अपीलांटस जिनकी आगे खरीदशुदा भूमि है रास्ता मांग रहे थे। उक्त किलो मे रास्ता देने से इन्कार कर दिया कि उक्त किलो मे कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है ना ही उक्त किले पत्थर लाईन पर है। रास्ता देने से मेरे एक खेत के दो खेत हो जायेगें तो अप्रार्थीगण/अपीलांटस कहने लगे कि रास्ता नहीं दोगे तो जबरदस्ती आपके उक्त किलो मे से रास्ता ले लेंगे। रेस्पो० की उक्त भूमि कि.न. 18, 19, 20 मे स्वीकृत या चालू रास्ता नहीं है। रेस्पो० ने उक्त किलो मे ग्वार की फसल काशत कर रखी है। अपीलांटस जबरदस्ती आवागमन करने से रेस्पो० की फसल नष्ट हो जायेगी व रेस्पो० की कृषि भूमि विभाजित हो जायेगी। इसी आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत कर अपीलांटस/अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा गया कि प्रार्थीगण की भूमि चक 6 डीएलपी के खाता सं. 19/18 के प.न. 143/194 मु.न. 48 कि.न. 18, 19, 20 मे आवागमन से निषेध रहे व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2017 को अन्तरित आदेश पारित किया गया जिसे अपीलाधीन आदेश के जरिये ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया है जो सही है। अपीलांटस ने बिना किसी आधार पर के अपील प्रस्तुत की है जो काबिले खारिज है।

6. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट का तर्क है कि “चक 6 डीएलपी के प.न. 143/194 मु.न. 48 की 8 बीघा भूमि वर्ष 2001 मे खातेदारान हरनेकसिंह, टेकसिंह व करनैलसिंह उर्फ फरनैलसिंह पुत्रगण जोगेन्द्रसिंह

के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित थी जो उक्त तीनों खातेदारों द्वारा दिनांक 30.04.2001 को गुरतेजसिंह पुत्र खेतासिंह को सप्रतिफल विक्रय कर दी तथा उक्त भूमि की पूर्व दिशा की ओर पत्थरलाईन अर्थात् प.न. 142/194 में अवस्थित मंजूरशुदा रास्ते से आने हेतु उक्त 8 बीघा भूमि को कोई रास्ता नहीं लगता था। उक्त भूमि क्रेता गुरतेजसिंह द्वारा विक्रय अनुबंधित भूमि जो प.न. 143/194 के मु.न. 48 कि.न. 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 में अवस्थित था, तत्पश्चात् दिनांक 15.05.2002 को हरनेकसिंह आदि द्वारा एक विक्रय विलेख गुरतेजसिंह के पक्ष में निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया। उक्त भूमि में आने जाने हेतु एक अन्य खातेदार गुलाम फरीद पुत्र अब्दुल हक जिसकी भूमि भी इसी मुरब्बा नं. 48 के कि.न. 18, 19, 20 में अवस्थित थी, में से उत्तर दिशा की ओर उक्त क्रेता गुरतेजसिंह द्वारा उक्त भूमि में आने जाने हेतु तीनों बीघों में दो दो बिस्वा भूमि यानि कुल 6 बिस्वा गुलाम फरीद से प्रतिफल क्रय कर ली जिसका पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 25.02.2002 को गुलाम फरीद बहक गुरतेजसिंह उपपंजीयक संगरिया कार्यालय से पंजीबद्ध करवा दिया। विक्रय विलेख के रोज से ही उक्त भूमि पर काबिज होकर रास्ता के रूप में अपनी खातेदारी भूमि का व्यक्तिगत रूप से उपयोग व उपभोग करने लगा तथा उक्त दोनों विक्रय विलेखों के आधार पर उक्त 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि का नामान्तरण भी गुरतेजसिंह के नाम से हो चुका है तथा गुलाम फरीद द्वारा दिनांक 25.02.2002 को एक हल्फनामा रोबरू गवाहान लिखवाकर निष्पादित किया कि चक 6 डीएलपी के प.न. 143/194 मु.न. 48 कि.न. 18, 19, 20 में 2-2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा भूमि गुरतेजसिंह पुत्र खेतासिंह को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख विक्रय की है तथा उक्त वर्णित रकबे का कब्जा सौंपा है तथा यह रकबा क्रेता द्वारा रास्ते के लिए क्रय किया है, बाबत दिया। तत्पश्चात् दिनांक 28.01.2005 को गुरतेजसिंह द्वारा उक्त दोनों बैयनामों में क्रय की

आराजी अप्रार्थी सं. 2/अपीलांट सं. 2 को विक्रय अनुबंधित कर कब्जा कुल भूमि का मौके पर उसी दिन अप्रार्थी सं. 2 को सौंप दिया तथा दिनांक 17.03.2007 को विक्रय विलेख अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया।”

7. अपीलांट के तर्क के खण्डन में रेस्पो0 का तर्क है कि “चक 6 डीएलपी के खाता सं. 19/18 में प.न. 143/193 मु.न. 30 कि.न. 22 ता 24/0.759 है0, प.न. 143/194 मु.न. 48 कि.न. 9 ता 12/1.012, 18/0.127, 19 ता 22/1.012, प.न. 144/195 मु.न. 50 कि.न. 21 ता 24/1.012, 25/0.228 है0, 143/196 मु.न. 61 कि.न. 4 ता 7/1.012, 14, 15/0.506 है0, 144/196 मु.न. 62 कि.न. 1 ता 4/9/2, 5/0.202, 6/0.228, 7 ता 14/2.024, 15/0.228 कुल 2.262 है0 रास्ता मय गै.मु. 0.102 खाला 0.126 है0 कुल 9.490 है0 भूमि है। उक्त भूमि रेस्पो0 के पिता गुरजन्तसिंह की खरीदशुदा है। रेस्पो0 के पिता गुरजन्तसिंह फौत हो चुका है उनके बाद समस्त भूमि रेस्पो0 के कब्जा में चली आ रही है। उक्त भूमि में प.न. 143/194 मु.न. 48 कि.न. 18/0.127, 19/0.253, 20/0.253 पूरे हैं। इनके से कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है लेकिन अपीलांटस जिनकी आगे खरीदशुदा भूमि है रास्ता मांग रहे थे। उक्त किलो में रास्ता देने से इन्कार कर दिया कि उक्त किलो में कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है ना ही उक्त किले पत्थर लाईन पर है। रास्ता देने से मेरे एक खेत के दो खेत हो जायेंगे तो अप्रार्थीगण/अपीलांटस कहने लगे कि रास्ता नहीं दोगे तो जबरदस्ती आपके उक्त किलो में से रास्ता ले लेंगे। रेस्पो0 की उक्त भूमि कि.न. 18, 19, 20 में स्वीकृत या चालू रास्ता नहीं है। रेस्पो0 ने उक्त किलो में ग्वार की फसल काशत कर रखी है। अपीलांटस जबरदस्ती आवागमन करने से रेस्पो0 की फसल नष्ट हो जायेगी व रेस्पो0 की कृषि भूमि विभाजित हो जायेगी।”

8. अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांत ने चक 6 डीएलपी के प.न. 143/194 मु.न. 48 कि.न. 18, 19, 20 में 2-2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा भूमि खरीदशुदा होने तथा उक्त 6 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु उपयोग व उपभोग करने का कथन किया है परन्तु उक्त भूमि का कब्जा अपीलांत का है, इसके संबंध में कोई दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है तथा ना ही बैयनामा में किला नम्बर व मुरब्बा नम्बर का उल्लेख किया है। चक 6 डीएलपी के प.न. 143/194 मु.न. 48 कि.न. 18, 19, 20 सांझा खाते में दर्ज है तथा संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक हिस्से पर स्वामित्व होता है। सहखातेदार के अलग अलग हिस्से का निर्धारण खाता विभाजन से ही हो सकता है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध में खाता विभाजन का दावा जैरकार है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 में बिना विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने के कारण अपील अपीलांतस खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है।
9. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़